



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 105-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 10, 2025 (JYAISTHA 20, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2025

**संख्या 31/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2025.**—हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब मीठा (उत्पादन) नियम, 1955, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम पंजाब मीठा (उत्पादन) हरियाणा संशोधन नियम, 2025 कहे, जा सकते हैं।  
(2) ये जून, 2025 के बारहवें दिन से लागू होंगे।
2. पंजाब मीठा (उत्पादन) नियम, 1955 में, नियम 4 में,—
  - (i) खण्ड (iii) में, “5,000”, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, “20,000”, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
  - (ii) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) हरियाणा राज्य में वाइनरी स्थापित करने के लिए आवेदक द्वारा अपना संयंत्र स्थापित करने से पूर्व आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। वैधता की विनिर्दिष्ट अवधि के साथ कतिपय निबन्धनों तथा शर्तों सहित आशय पत्र जारी किया जाएगा। यह सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा। आशय पत्र के लिए फीस प्रथम बार के लिए एक लाख रुपये होगी। वाइनरी के स्थापित करने के लिए आशय पत्र के पुनः विधिमान्यकरण के लिए फीस पिछले वर्ष की फीस का 110 प्रतिशत होगी:

परन्तु आशय पत्र धारक आवेदक को आशय पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर संयंत्र स्थापित करना होगा, ऐसा न करने पर इसे रद्द समझा जाएगा।”;
  - (iii) खण्ड (iv) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) आबकारी आयुक्त द्वारा ₹1,00,000/-के भुगतान पर प्ररूप अनु0-1 डब्ल्यू में अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीनीकृत की जाएगी। अनु0-1 डब्ल्यू अनुज्ञप्तिधारी राज्य के अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी आपूर्ति करेगा।

- (ख) राज्य की स्थानीय वाइनरी को वाइन की खुदरा बिक्री के लिए प्ररूप एस0-1क में अनुज्ञप्ति ₹20,000/ के भुगतान पर दी जाएगी ताकि वाइनरी के आस-पास के परिसर में वे अपने स्वयं के स्वदेशी रूप से निर्मित उत्पादों को बेच सकें।
- (ग) प्ररूप एस0-1ख में अनुज्ञप्ति एस0-1क अनुज्ञप्ति धारक को ₹5,000/ के भुगतान पर प्रदान की जाएगी।”।

आशिमा बराड,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th June, 2025

**No. 31/X-1/P.A.1/1914/S.59/2025.**— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Sweets (Manufacture) Rules, 1955, in their application to the State of Haryana, namely :-

1. (1) These rules may be called the Punjab Sweets (Manufacture) Haryana Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force with effect from the 12<sup>th</sup> day of June, 2025.

2. In the Punjab Sweets (Manufacture) Rules, 1955, in rule 4,-

- (i) in clause (iii), for figure and sign “5,000”, the figures and sign “20,000” shall be substituted;
- (ii) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) A letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a Winery in the State of Haryana before he starts putting up his plant. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a specified period of validity. It shall be issued with the permission of Government. Fee for letter of intent shall be rupees one Lakh for the first time and the fee for revalidation of subsequent extension of letter of intent for setting up winery shall be 110% of the previous year’s fee:

Provided that the applicant holding Letter of Intent shall have to set up the plant within three years from the date of issue of Letter of Intent, failing which it shall be deemed cancelled.”;

- (iii) after clause (iv), the following clauses shall be inserted namely:-

- “(a) A license in form L-1W shall be granted/renewed on the payment of ₹1.00 Lakh by the Excise Commissioner. The L-1W licensee shall make its supplies to the L-1 licensees of the State.
- (b) A license in form S-1A for retail sale of wine shall be granted on the payment of ₹20,000/- to the local wineries of the State for selling their own indigenously manufactured products in the adjoining premises of the winery.
- (c) A license in form S-1B shall be granted on the payment of ₹5,000/- to the license holder of S-1A license.”.

ASHIMA BRAR,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.